MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

मोदी युग में संघवाद : समावेशी विकास का उभरता स्वरूप

डॉ. सिद्धार्थ राव
सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)

डॉ. भावना
सहायक आचार्य (इतिहास)
राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)

शोध सार

भारत के विशाल आकार, विविध भौगोलिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक बाध्यताओं के कारण संविधान निर्माताओं ने भारत को संघात्मक स्वरूप प्रदान किया। संघीय ढांचे के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है तद्नुरूप आपसी सम्बन्धों का भी निर्धारण होता है। भारत में संसदात्मक शासन एवं बहुदलीय प्रणाली ने भी संघवाद को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। स्वाधीनता प्राप्ति से लेकर अब तक संघवाद के अनेक प्रतिमान सामने आए हैं जिन्हें सहयोगी, एकात्मक या सौदेबाजी वाले संघवाद के रूप में समझा जा सकता है। 21वीं सदी में विशेषतः 2014 से 2024 तक का समय जिसे हम मोदी युग भी कह सकते हैं, संघवाद की दृष्टि से राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर लेकर गया जिससे राष्ट्र में संघवाद के समावेशी विकास का स्वरूप उभरकर सामने आया है। इसने देश के लोकतांत्रिक संघवाद को ओर अधिक परिपक्व और मजबूत किया है। आज भारत के सभी राज्यों में समान रूप से विकास को बढ़ावा मिल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी और श्रीगंगानगर से ईटानगर तक इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। आज पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न केन्द्रीकृत योजनाओं ने देश के सभी क्षेत्रों व राज्यों में समानता पर आधारित विकास को आगे बढ़ाया है। जिसके कारण आज केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में सहयोग, सहकारिता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को मजबूती मिल रही है जो कि देश में समावेशी विकास पर आधारित संघवाद की दिशा की ओर महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रस्तुत शोध पत्र में मोदी सरकार (2014–2024) के शासनकाल के दौरान भारतीय संघवादी व्यवस्था में समावेशी विकास के उभरते स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का एक प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः संघवाद, केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, समावेशी विकास, सहयोग, सहकारिता, केन्द्रीकृत, प्रतिस्पर्धा

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

भूमिका–

संघीय शासन की सफलता केन्द्र–राज्य संबंधों एवं इकाईयों के विकास पर ही आधारित होती है। संघीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्य सरकारें अपने–अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं किन्तु भारत जैसे देशों में जहाँ शक्ति विभाजन में केन्द्र की शक्तियाँ ज्यादा है, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकारों का उत्तरदायित्व इकाईयों के प्रति ज्यादा हो जाता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार की स्थिति मजबूत होनी चाहिए ना कि गठबंधन की कमजोर सरकारों जैसी। 21वीं सदी में 2014 से 2024 तक का समय संघीय विकास की दृष्टि से एक ऐसा समय है जो कि भारतीय संघवाद को एक नई दिशा की ओर लेकर गया। 2014 से पूर्व की परिस्थितियों में कभी बहुमत न मिलने, कभी गठबंधन के कारण संघीय व्यवस्था पर पकड़ कमजोर हो रही थी, क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते दखल के कारण केन्द्र उनकी दया पर निर्भर था। ऐसी स्थिति में सौदेबाजी व विवादपूर्ण संबंधों के चलते पूर्व की सरकारों का ध्यान समावेशी विकास की ओर गया ही नहीं। सन् 1984 से 2014 तक का दौर सौदेबाजी व अस्थिरता का था, यहाँ दो तरफा सौदेबाजी नजर आई एक तो केन्द्र व राज्यों के मध्य और दूसरा राज्यों की आपसी खींचतान। इस 2014 से पूर्व के दौर में हर एक राज्य व क्षेत्रीय दल अपने–अपने स्तर पर अपने हितों की पूर्ति व क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत था। ऐसे में कुछ मजबूत क्षेत्रीय दलों द्वारा कुछ राज्य ही फायदा ले पाए। यहाँ सहयोगी संघवाद व समावेशी विकास जैसी स्थिति नजर नहीं आई। 2014 से पूर्व में भारत की संघीय व्यवस्था संविधान और संविधान बनाने वालों के मंतव्य के विपरीत दिशा में विकसित हो रही थी। यदि 2014 में सुसंगठित एनडीए की सरकार ना बनी होती तो भारतीय संघ धीरे–धीरे एक कमजोर संघ व्यवस्था में बदल जाता। देश में राजनीतिक सत्ता बदलने के साथ ही विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय स्तर पर कड़े परिवर्तन मोदी सरकार द्वारा किये गये हैं जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री केन्द्र व राज्यों को परस्पर प्रतिस्पर्धी के स्थान पर मित्र व सहयोगी बनाने के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में कामकाज संभालने के बाद कहा था कि वे केन्द्र व राज्यों के बीच की खाई को पाटना चाहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्राप्त तजुर्बे का जिक्र करते हुए उन्होनें राज्यों से ऐसा ढांचा बनाने की अपील की जिसमें सहकारी व सहयोगात्मक संघवाद के जरिये सभी लोगों के लिए समावेशी विकास की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। देखा जाये तो इन दस वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने देश की एकता व अखण्डता के साथ–साथ राज्यों को साथ लेकर केन्द्रीकृत योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी विकास को नई दिशा प्रदान की है। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि बिना राज्यों के सहयोग के सफल व विकसित संघवाद और समावेशी विकास की बात नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों में– "मैं भलीभांति जानता हूँ कि देश की ताकत राज्यों में निहीत है जो राज्यों की ताकत समझता है वही देश को समझ सकता है। भारत को आगे बढना है तो राज्यों को आगे बढना आवश्यक है''। ऐसी स्थिति में संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों में होने वाला समावेशी विकास ही देश की एकता व अखण्डता को बनाये रखते हुए, विकास व शांति की राह दिखा सकता है। इस अवधि में देश में समावेशी विकास के सर्वोत्तम अवसर व प्रयास नजर आये। इसके दो मुख्य कारण रहे एक तो केन्द्र में भाजपा को प्राप्त स्पष्ट बहुमत के कारण क्षेत्रीय दलों का

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

दबाव केन्द्र पर नजर नही आया और दूसरा श्री नरेन्द्र मोदी का गुजराज के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य का लम्बा अनुभव। मोदी युग में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीकृत योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल संघीय व्यवस्था को सहकारिता व सहयोग के आधार पर चलाया बल्कि इनके माध्यम से राज्यों में समेकित विकास का स्वरूप भी उभरकर सामने आया, जिसे निम्न बिन्दुओं के आधार पर देखा व समझा जा सकता है–

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना–

मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में वित्तीय समावेशन को महत्व देते हुए इस योजना की शुरूआत अगस्त 2014 में की गयी। यह सभी राज्यों में समान रूप से गरीबी उन्मूलन की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसके माध्यम से आम जनता तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच का आश्वासन संभव हो पाया। काफी समय से आम आदमी के सशक्तिकरण हेतु एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जो सभी के लिए समान रूप से सर्व सुलभ हो और केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का फायदा अन्तिम व्यक्ति तक सभी राज्यों में समान रूप से पहुँच सके। इस योजना के माध्यम से सहयोगी संघवाद और उसमें समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए शुरूआत से ही भिन्न राज्यों को इससे जोड़ा गया। इसके उद्घाटन के दिन ही 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देशभर में 600 कार्यक्रमों एवं 77852 शिविरों के साथ इसमें शिरकत की। इसका उद्देश्य था लोगों को बैंक खाते से जोड़ना ताकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं सब्सिडी का फायदा सीधे लोगों तक पहुँचे। इस योजना के अन्तर्गत 1.50 करोड़ बैंक खाते पहले ही दिन खोले गये साथ ही स्वदेशी रूपे डेबिट कार्ड भी खाताधारक को मुफ्त दिये गये। इस योजना से करोड़ो लोगों को फायदा हुआ, ऐसे लोग जिनका बैंकिग सुविधाओं से कोई लेना–देना नहीं था जो इस सुविधा से अनजान थे, उन्हें ऐसी सुविधा से जोड़ा गया जिसके कारण सरकारों द्वारा प्राप्त होने वाली सब्सिड़ी एवं वित्तीय लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे आम व्यक्ति तक पहुँच सके। इस योजना से न केवल सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला बल्कि लोगों की वित्तीय क्षमता में वृद्धि के चलते समावेशी विकास में भी मदद मिली। इस सुविधा के अन्तर्गत शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये। आज देश में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 51 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं जिसमें 2.08 ट्रिलियन रूपये जमा हैं। इससे कोविड–19 के समय भी समावेशी विकास को बनाए रखने में मदद मिली। ऐसे विकट समय में सरकार द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह दी जाने वाली 500 रू. की राशि भी इन्हीं जनधन खातों में जमा की गई। इन खोले गये कुल खातों में 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। इससे गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण में भी काफी मदद मिली है। समावेशी विकास के लिए वित्तीय सुविधाओं की पहुँच प्रत्येक राज्य और आम आदमी तक होनी आवश्यक है और यह कार्य इस योजना के माध्यम से ही हो पाया है।

2. सांसद आदर्श ग्राम योजना–

देश में समावेशी विकास तभी संभव है जब प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र तक विकास की पहुँच सुनिश्चित हो, साथ ही उसमें क्षेत्र एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी भी शामिल हो। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा अक्टूबर–2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयन्ती पर आरम्भ की गयी। आज भी वास्तविक भारत और अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, इसलिए आवश्यक है कि विकास अन्तिम व्यक्ति तक और गांव–गांव तक पहुंचे क्योंकि अभी भी भारत के बहुत से गांवों में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। ऐसी स्थिति में वहां विकास की बात करने से पहले बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आवश्यक है। यह एक ऐसी योजना है जो कई उदेश्यों को पूरा करती है इसके अन्तर्गत 2024 तक प्रत्येक सांसद आठ गाँवों से जुड़कर उनके विकास के भागीदार बनेगें एवं गाँव में ढ़ांचागत विकास हो सकेगा। इस योजना में लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद शामिल है। इससे संघवाद को मजबूती मिलेगी एवं समावेशी विकास अपने पूर्ण अर्थों में सार्थक होगा। आज लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर कुल लगभग 800 सांसद है। इस योजना से 2014 से 2024 तक 6000 से भी अधिक आदर्श ग्राम बन सकेगें। इससे जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन में सुधार आयेगा, ग्राम पंचायतों का ढ़ांचागत एवं समग्र विकास होगा, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र में असमानता कम होगी, सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता आएगी। स्वंय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत बनारस से 25 कि.मी. दूर जयापुर गांव को गोद लिया गया है। इस योजना में केन्द्र को राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडू, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड जैसे अनेक राज्य अपना योगदान दे रहे हैं साथ ही इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा अपनी अनेक योजनाओं को इसके साथ जोड़ दिया है जैसे इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा के साथ–साथ सांसदों को मिलने वाले विकास फंड भी इसमें शामिल किए गए है ताकि यह योजना वास्तविक रूप से धरातल पर लागू हो सके। यह योजना अपने अन्तिम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुकी है यद्यपि अभी गोद लिए गये गांव में काम की गति 75 प्रतिशत से कम है किन्तु योजना के सकारात्मक उदेश्य को देखते हुए इसे आगे जारी रखा जा सकता है। गाँव–गाँव तक बुनियादी सुविधाओं एवं ढांचागत विकास के माध्यम से इस योजना ने देश के समावेशी विकास में अपना योगदान दिया है।

3. श्रमेव जयते योजना–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु 16 अक्टूबर 2014 को 'श्रमेव जयते' योजना की घोषणा की गयी। यह योजना उन लाखों मजदूरों को सुविधा देने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की गई जो विभिन्न संगठित और असंगठित क्षेत्रों में देश के विकास हेतु अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के समुचित विकास में यह योजना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें श्रम को और श्रमिकों को उचित दर्जा देते हुए उन्हें लेबर आंइडिफिकेशन नम्बर दिया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसी भी कार्य को सुचारू ढ़ंग से चालू करना, रोजगार बढ़ाना व उस रोजगार से जुड़े हुए सभी श्रमिकों के कल्याण से जुड़ा था तथा इस योजना में भारत में समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि इन श्रमयोगीयों के द्वारा ही हम आने वाले समय में भारत को मजबूती प्रदान कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत श्रम क्षेत्र में सुधार का लक्ष्य रखा गया ताकि श्रमिक वर्ग भी देश और राज्यों के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकें और विभिन्न राज्य और इकाईयां मिलकर देश में समावेशी विकास को बढ़ावा दे सके और

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

भारत निरन्तर ऊचाईयों तक बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इससे देश में सहयोगी संघवाद भी मजबूत होगा। इसे मजबूती प्रदान करने हेतु अभी हाल ही में 25–26 अगस्त 2022 को केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आन्ध्रप्रदेश के तिरूपति में रखा गया जिसका मुख्य उदेश्य था देश में सहयोगी संघवाद को सुढ़ृढ़ करना तथा समावेशी विकास को गति प्रदान करना। इससे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्र व राज्य सरकारों ने मिल कर चर्चा की।

4. राष्ट्रीय आयुष मिशन–

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में अपने कार्यग्रहण के पश्चात् निरन्तर इस बात पर जोर दिया गया कि देश में संघवाद के विकास हेतु और राज्यों के समावेशी विकास हेतु केन्द्र सरकार किस प्रकार अपना योगदान दे सकती है। इस हेतु राज्यों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ प्रारम्भ की गयी ताकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं व ढ़ांचागत विकास को गति प्रदान कर राज्यों के विकास को सुढ़ृढ़ किया जा सके जिससे देश में सहकारी संघवाद की भावना विकसित हो सके। इसी कड़ी में राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरूआत सितम्बर 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा की गयी। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारम्भ किया गया। इसके जरिये देश में एलोपेथी चिकित्सकों की कमी को पारम्परिक चिकित्सा पद्धति द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया ताकि राज्यों में स्वास्थ्य योजनाओं को और अधिक विकसित किया जा सके। इसके अन्तर्गत राज्यों में पारम्परिक चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। केन्द्र सरकार ने जुलाई 2021 में इस योजना को 2026 तक जारी रखने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।

5. ह्रदय योजना–

मोदी सरकार द्वारा नये–नये प्रयोगों के तहत देश की विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु व विभिन्न राज्यों के विकास हेतु उनमें पर्यटन की सम्भावनाओं को देखते हुए 21 मई 2015 राष्ट्रीय विरासत एवं संवर्धन योजना HRIDAY का शुभारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों का जो अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते है के विकास और संवर्धन का लक्ष्य रखा गया। उन्हें स्मार्ट और स्वच्छ बनाने पर जोर दिया गया ताकि देश में पर्यटन के नये अवसर विकसित हो सके।

इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख शहरों के चयन में उस सम्बन्ध में योजना, प्रबंधन और कार्यान्वयन को निर्धारित करने में केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ विचार–विमर्श किया तथा साझेदारी में सम्पूर्ण रणनीति बनायी जिससे केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में निकटता उत्पन्न हुई। देश में सहयोगी संघवाद को मजबूती प्राप्त हुई और इसी के फलस्वरूप देश में विभिन्न राज्यों के समावेशी विकास में सहायता प्राप्त हुई। इस योजना के प्रथम चरण में 12 शहरों को चुना गया जो अमरावती, अमृतसर, अजमेर, गया, द्वारका, बदामी, कांचीपुरम्, मथुरा, पूरी, वाराणसी, वेलोकन्नी तथा बांरगल है। इस योजना

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

का बजट 500 करोड़ रूपये निर्धारित कर इन सभी शहरों के विकास का लक्ष्य रखा गया जिससे इन शहरों मे पर्यटन की सम्भावनाएँ बढ़ेगी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें।

6. स्मार्ट सिटी योजना–

विभिन्न राज्यों के विकास को देखते हुए मोदी सरकार द्वारा विभिन्न शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु व वहां के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से देश के 100 शहरों को "स्मार्ट सिटी" में बदलने की योजना प्रारम्भ की गयी। यह योजना लोगों के जीवन स्तर में सुधार के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस मिशन को सफल बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक शहर को औसतन 100 रू. वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाने का लक्ष्य रखा गया जिसमें से प्रत्येक राज्य भी 50 करोड़ रू. वित्तीय सहायता के रूप में अपना अंशदान करेगें। इस योजना के अन्तर्गत शहरों के चयन की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वस्थ सहकारी प्रतिस्पर्द्धा को आवश्यक माना जिससे कि देश अपने राज्यों के साथ मिलकर समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। इन 100 शहरों में पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के शहर शामिल है तथा इस योजना में राज्यों की स्वायत्तता का ध्यान रखते हुए सहयोगी संघवाद की दिशा में कदम बढाये जा रहे है।

7. सेतु भारतम योजना–

मोदी काल में संघवाद जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उससे केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में सुधार तो हो ही रहा है साथ ही राज्यों का समावेशी विकास भी संभव हुआ है और विभिन्न राज्य एक–दूसरे के साथ अधिक सम्पर्क में आये है। इसी के तहत विभिन्न राज्यों में आपसी सहयोग व समन्वय बढ़ाने हेतु तथा राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु मोदी सरकार द्वारा 04 मार्च 2019 को सेतु भारतम् परियोजना लॉन्च की गयी। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में 208 रेल अंडर और ओवर ब्रिज विकसित करना तथा जर्जर पुलों की मरम्मत करना था ताकि यात्रियों के लिए आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इससे विभिन्न राज्यों के भिन्न–भिन्न शहरों का आपस में जुड़ना आसान हुआ है जिससे देश में विभिन्न राज्यों में आपस में सम्पर्क भी बढ़ा है।

8. नीति आयोग का निर्माण–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में न केवल सहकारी संघवाद और राज्यों के बीच आपसी सहयोग व समन्वय की बातें करते है बल्कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु यथासंभव उन्होनें प्रयास भी किया है और इसी के अन्तर्गत उन्होनें योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भूमिका को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु व राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु नीति आयोग का गठन 5 जनवरी 2015 को किया जिसे सरकारी थिंक टैंक कहा गया तथा उम्मीद जतायी गयी कि यह भविष्य में राज्यों से विचार–विमर्श कर उनके समावेशी विकास हेतु योजनाएँ निर्धारित करने में सरकार का सहयोग करेगा। इसी के तहत मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया क्योंकि योजना आयोग से राज्यों को बहुत शिकायतें रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार मजबूत राज्य ही मजबूत संघ का निर्माण कर सकते हैं और इसी के तहत दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु नीति आयोग का

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

गठन किया गया है। 'सहकारी संघवाद' स्थापित करने की दिशा में मोदी सरकार का यह क्रान्तिकारी कदम माना जा सकता है।

9. मेक इन इण्डिया–

देश के विभिन्न राज्यों के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए उनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु तथा रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'मेक इन इण्डिया' प्रोग्राम 25 सितम्बर 2014 को प्रारम्भ किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाये जाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे एफडीआई को बढ़ावा मिला तथा भारतीय रूपये को भी मजबूती मिली है जिससे देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार की सम्भावनाएँ बढ़ी व पूँजी का प्रवाह बढ़ा है। दुनिया के 101 देशों ने अब तक भारत के 31 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अलग–अलग 57 क्षेत्रों में निवेश किया है जिससे राज्यों में आर्थिक विकास को गति मिली है। अभी तक एफडीआई 83 अरब डॉलर का हो गया है जिसे मेक इन इंडिया 2.0 कार्यक्रम में 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

10. पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति शान्ति स्थापना की नीति–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ाने हेतु देश के सभी राज्यों के समावेशी विकास को ध्यान में रखा तथा इसी उदेश्य की प्राप्ति हेतु पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो कि देश की मुख्यधारा में शामिल न होकर सदियों से उपेक्षित व्यवहार सहन कर रहे थे तथा निरन्तर हिंसा से वहां के नागरिक पीड़ित थे शान्ति स्थापना के प्रयास किये गये। वहां बुनियादी ढांचे का विकास किया गया तथा इन राज्यों में मोदी सरकार के प्रयासों से उग्रवाद की घटनाओं में भी कमी आयी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता सम्भालने के बाद से ही इन राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया। इनकी कनेक्टीविटी को बढ़ाया, हवाई अड्डो की संख्या बढ़ायी गयी, सड़कें बनायी गयी जिससे इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित हुये। मोदी सरकार के सता में आने के बाद इन राज्यों में शान्ति स्थापित हुई है। केन्द्र सरकार ने असम के 60 प्रतिशत क्षेत्रों से विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) हटा लिया तथा पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में इसे सीमित कर दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शान्ति स्थापना के प्रयासों के तहत मणिपुर और असम के उग्रवादी संगठन क्रमशः UNLF तथा ULFA के साथ केन्द्र सरकार ने 29 नवम्बर 2023 व 29 दिसम्बर 2023 को शान्ति समझौता किया जिससे इन संगठनों ने हिंसा छोड़ने तथा समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की बात स्वीकार की है। इससे इन राज्यों में हिंसा की गतिविधियों में कमी आयेगी तथा इनके विकास के नये अवसर उपलब्ध होगें।

निष्कर्ष–

भारतीय संघीय व्यवस्था में 21वीं सदी में 2014 से 2024 तक का मोदी सरकार का यह मार्ग अनेक चुनौतियों व संकटों के दौर से गुजरा। इस दौरान न केवल आंतरिक चुनौतियों बल्कि कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी जैसे महान संकटों का सामना भी देश को करना पड़ा। बावजूद इसके देश में मोदी सरकार को 2014 से 2019 के बाद पुनः 2019 से 2024 के लिए पूर्ण बहुमत का

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

मिलना इस बात का संकेत है कि सरकार के कार्यों को जनादेश ने अपनी सहमति दी है और विश्वास दिखाया है। निःसन्देह संघवाद में समावेशी विकास को बढ़ाने हेतु जैसी केन्द्रीकृत योजनाएं व नीतियां इस समयावधि में नजर आई वैसी पूर्व के वर्षों में नहीं देखी गई। यही कारण रहा कि देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय संघ की साख बढ़ी है। देश ने विश्व के न केवल UNO बल्कि क्षेत्रीय संगठनों SAARE, G-20 जैसे संगठनों में अपनी मजबूत व विकास की ओर बढ़ते संघ की छवि कायम की है। प्रधानमंत्री का पहले दिन से अपने पूर्व के प्राप्त अनुभव के आधार पर मानना था कि संघ की प्रवृत्ति सहयोगी, सहकारी व सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए और सभी राज्यों में समान विकास किया जाना चाहिए तभी देश की वास्तविक तरक्की होगी। प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा कि देश में कुछ राज्य व क्षेत्र ऐसे है जहाँ विकास तो दूर मूलभूत व बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, ऐसे में जब तक सभी राज्यों व क्षेत्रों में समान विकास न होने की स्थिति में मजबूत व विकसित संघवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज केन्द्र सरकार के इन 10 वर्षों (2014–2024) के समय में उपरोक्त केन्द्रीकृत विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ समावेशी विकास साफ नजर आता है। 2014 से पूर्व आम नागरिक पूर्वोतर की एक अलग ही दृष्टि से देखता था किन्तु आज पूर्वोतर राज्यों में विकास व पर्यटन के मार्ग प्रशस्त हुए है। जम्मू–कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर धारा–370 हटा दी गयी है और उसे विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया है, साथ ही आतंकवाद अपने न्यूनतम स्तर पर है अब वहाँ विकास देखने लायक है। ऐसे ही कश्मीर से कन्याकुमारी व श्रीगंगानगर से ईटानगर तक एक समान व समावेशी विकास साफ नजर आ रहा है। देश में हुए तीव्र आर्थिक विकास ने न केवल राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है बल्कि दूसरी तरफ 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' एवं 'टीम इंडिया' जैसे कार्यक्रमों व विचारों ने संघीय व्यवस्था को मजबूत किया है। निःसन्देह मोदी युग में भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों में समावेशी विकास का स्वरूप तेजी से उभरकर सामने आया है।

संदर्भ

1. द इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, मई–29, 2020
2. कोठारी, रजनी (2017), भारत में राजनीति दल और आज, वाणी प्रकाशन दरियांगज, नई दिल्ली
3. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, जून–1, 2020
4. सईद, एम.एम., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ
5. बलवीर अरोड़ा (फरवरी–2015) 'वित्तीय संघवादः सीखे व अनसीखे कदम', सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, योजना पत्रिका, नई दिल्ली
6. अनुज कुमार अग्रवाल (फरवरी–2015), 'संघ व राज्यों के आर्थिक सम्बन्धों की पुर्नव्यवस्था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, योजना पत्रिका, नई दिल्ली
7. प्रतियोगिता दर्पण, जुलाई–2014, पृ–14, 20
8. Narender Modi's vision of cooperation federalism, www.hindustan times.com translate. Goog

MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal
ISSN: 1053-7899
Vol. 35 Issue 1, Jan-June 2025, Pages: 32-40

9. To achieve meuier Hights of devlopments, pm calls for cooperative federlisam, www.thehindubusinessline.com translate.goog
10. प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर 2014, पृ.—27
11. https://hi.vikaspedia.in/Social-welfare
12. https://hindi.economictimes.com/wealth/pessand - finance what- is- sansad. aadrash -gram-yojana/article now/63925.com
13. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2014, पृ. 20
14. Shramev Jayate Yojana-wikipedia
15. https://www.pratinidhimanthan.com/government-scheme/12-Lities-will be- Urbanized-under-hriday-yojana-know-the complete-details-of-the-plan
16. https://navbharattimes.indiatimes.com/india/what-is-smart.in.smart-city-mission- its- adveniages-and-total-cities-in-this-list-know-all-details-here/articlehow/97856385.com Urbanized-under-hriday-yojana-know-the complete-details-of-the-plan
17. https://www. squareyards.com.translate.goog/blog/setes bharatam. Project . gov.
18. प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2015, पृ. 89
19. https://www.gyanipandit.com/make-in-india
20. https://www.bhaskar.com/national/news/Unif-peace-deal.anit.shah. Narender .modi.assam-government-132362961.com
21. https://www.india.com.translate.goog/news/india.9-year of pm-modi-how-modi-govt-changed-the-face-of-northeast-and-it-india-now-hub-60767461/?